



PADMABHUSHAN VASANTRAODADA PATIL MAHAVIDYALAYA
KAVATHE MAHANKAL, Dist. Sangli (Maharashtra) Pin- 416 405
Principal Prof. (Dr.) M. K. Patil M.Sc., M. Phil., Ph.D. Mob.9421185277
Phone-02341-295220 Email: kmpvp@rediffmail.com Website: www.pvpkm.ac.in
Jr. College Index No. J 22.04.002

Criterion-5: Student Support and Progression

Key Indicator 5.1 Student Support

5.1.4 The institution adopts the following for redressal of student grievances including sexual harassment and ragging cases

Implementation of guidelines of statutory/regulatory Bodies and circulars




PRINCIPAL,
Padmabhushan Vasanttraodada Patil
Mahavidyalaya, K. Mahankal, Dist- Sangli



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 6, 2019/वैशाख 16, 1941

No. 146]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 2019/VAISAKHA 16, 1941

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2019

फा. सं. 14-4/2012 (सीपीपी-II).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 का अधिक्रमण करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

1. संक्षिप्त नाम, विनियोग और प्रारंभ :

- (क) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2019 कहा जाएगा।
- (ख) वे ऐसे सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे, जिन्हें किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के तहत स्थापित अथवा निगमित किया गया हो, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के तहत मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों तथा ऐसे सभी सम विश्वविद्यालय संस्थानों पर लागू होंगे जिन्हें तत्संबंध की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो।
- (ग) यह विनियम, भासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. उद्देश्य:

किसी संस्थान में पहले से नामांकित छात्रों और साथ ही ऐसे संस्थानों में प्रवेश चाहने वाले छात्रों की कतिपय शिकायतों के निवारण के लिए अवसर प्रदान करना और इस संबंध में एक तंत्र स्थापित करना।

3. परिभाषा: जब तक कि इन विनियमों के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) "अधिनियम" का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) से है;
- (ख) "पीडित छात्र" से अभिप्राय किसी ऐसे छात्र से है जिसे इन विनियमों के तहत परिभाषित शिकायतों के संबंध में किसी मामले अथवा तत्संबंध किसी मामले में कोई शिकायत हो।

- (ग) "महाविद्यालय" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) में इस प्रकार से परिभाषित किसी संस्थान से है।
- (घ) "महाविद्यालयी छात्र शिकायत निवारण समिति" (सीएसजीआरसी) से अभिप्राय इन विनियमों के तहत किसी संस्थान के स्तर पर, जोकि महाविद्यालय हो, गठित किसी समिति से है।
- (ङ) "आयोग" से अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत स्थापित आयोग से है।
- (च) "घोषित प्रवेश नीति" का अभिप्राय संस्थान द्वारा पेशकश किए जा रहे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए संस्थान की विवरणिका में प्रकाशित की गई किसी ऐसी नीति से है, जिसमें उसके अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।
- (छ) "विभागीय छात्र शिकायत निवारण समिति" (डीएसजीआरसी) से अभिप्राय इन विनियमों के तहत किसी विश्वविद्यालय के किसी विभाग, विद्यालय या केंद्र के स्तर पर गठित किसी समिति से है।
- (ज) "शिकायत" का अभिप्राय, और इसमें निम्नवत् के संबंध में किसी पीड़ित छात्र द्वारा की गई शिकायत(तें) शामिल हैं, नामतः
- i. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप निर्धारित की गई योग्यता के विपरीत प्रवेश दिया जाना;
 - ii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत प्रक्रिया में अनियमितताएं;
 - iii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप प्रवेश देने से इंकार किया जाना;
 - iv. इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप, संस्था द्वारा विवरणिका का प्रकाशन न किया जाना;
 - v. संस्थान द्वारा विवरणिका में ऐसी कोई जानकारी देना जोकि झूठी या भ्रामक हो, और तथ्यों पर आधारित नहीं हो;
 - vi. किसी छात्र द्वारा ऐसे संस्थान में प्रवेश लेने के प्रयोजन से जमा किए गए किसी दस्तावेज जोकि उपाधि, डिप्लोमा या किसी अन्य पुरस्कार के रूप में हो, को अपने पास रख लेना या वापस करने से इंकार करना ताकि ऐसे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के संबंध में छात्र को किसी शुल्क अथवा शुल्कों, का भुगतान करने हेतु तैयार किया जा सके अथवा मजबूर किया जा सके जिसमें छात्र अध्ययन नहीं करना चाहता हो;
 - vii. संस्था की घोषित प्रवेश नीति में निर्धारित राशि से अधिक धनराशि की मांग करना;
 - viii. छात्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रवेश में सीटों के आरक्षण के संबंध में वर्तमान में लागू किसी कानून का संस्थान द्वारा उल्लंघन किया जाए;
 - ix. ऐसे किसी संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत, अथवा आयोग द्वारा विहित किन्हीं शर्तों, यदि कोई हों तो, के तहत किसी भी छात्र हेतु ग्राह्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का भुगतान नहीं किया जाना अथवा विलम्ब से भुगतान किया जाना;
 - x. संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर में, अथवा आयोग द्वारा विहित ऐसे किसी कैलेंडर में विनिर्दिष्ट अनुसूची से इतर परीक्षाओं के आयोजन में, अथवा परीक्षा के परिणामों की घोषणा में विलम्ब करना;
 - xi. विवरणिका में यथा उल्लिखित, अथवा संस्थान द्वारा लागू किसी कानून के किसी उपबंध के तहत यथा अपेक्षित छात्रों की सुविधा प्रदान करने में संस्थान द्वारा विफल रहना;
 - xii. छात्रों के मूल्यांकन के लिए संस्थान द्वारा अपनाई गई गैर- पारदर्शी अथवा अनुचित पद्धतियां;
 - xiii. ऐसे किसी छात्र को शुल्क के प्रतिदाय में विलंब करना, अथवा इंकार करना जोकि विवरणिका में उल्लिखित समय के भीतर, अथवा जैसा की आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए, के भीतर प्रवेश त्याग देता है;
 - xiv. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक अथवा निशक्त श्रेणियों के छात्रों के कथित भेदभाव की शिकायत;
 - xv. प्रवेश दिए जाने के समय जैसा भरोसा दिलाया गया था अथवा प्रदान किए जाना अपेक्षित था के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं किया जाना; तथा

- xvi. छात्र के उत्पीड़न के अन्य मामले के अलावा जिन पर वर्तमान में लागू किसी कानून के दंडात्मक उपबंधों के तहत कार्रवाई की जानी हो, छात्र का उत्पीड़न किया जाना अथवा उसे निशाना बनाया जाना।
- (झ) “संस्थान” से अभिप्राय है, जैसा कि संदर्भ हो, अधिनियम के तहत किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा किसी सम विश्वविद्यालय संस्थान से है, अथवा किसी विशिष्ट विधा अथवा क्रियाकलाप हेतु किसी विश्वविद्यालय के तहत स्थापित किए गए किसी संस्थान से है।
- (ञ) “संस्थागत छात्र शिकायत निवारण समिति” (आईएसजीआरसी) का अभिप्राय इन विनियमों के तहत किसी विश्वविद्यालय के स्तर पर, ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए गठित की गई समिति से है जो विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग से संबंधित नहीं हो, उदाहरण के लिए छात्रावास और सामान्य सुविधाएं।
- (ट) “लोकपाल” का अभिप्राय इन विनियमों के तहत नियुक्त लोकपाल से है;
- (ठ) “विवरणिका” का अभिप्राय और इसमें ऐसा कोई भी प्रकाशन शामिल है, चाहे वह मुद्रित स्वरूप में अथवा अन्यथा हो, जिसे जनसाधारण (जिसमें ऐसे संस्थान में प्रवेश पाने के इच्छुकों सहित) को एक संस्था से संबंधित निष्पक्ष और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए ऐसे संस्थान अथवा किसी प्राधिकरण अथवा ऐसे संस्थान द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया हो;
- (ड) “क्षेत्र” का अभिप्राय एक भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें राज्य शामिल हैं, जिन्हें इन विनियमों को लागू करने हेतु सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ ऐसा निर्धारित किया गया हो: नामतः, दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार और तमिलनाडु शामिल हैं; दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप शामिल हैं; पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव शामिल हैं; मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं; उत्तरी क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ शामिल हैं; पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड शामिल हैं, और पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं।
- (ढ) “राज्य” का अभिप्राय संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य से है जिसमें संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल है;
- (ण) “छात्र” से अभिप्राय किसी ऐसे संस्थान, जिसमें यह विनियम लागू होते हैं, में नामांकित किसी व्यक्ति, अथवा नामांकित होने के लिए प्रवेश प्राप्त के इच्छुक व्यक्ति से है;
- (त) “विश्वविद्यालय” से अभिप्राय अधिनियम की धारा 2 की खंड (च) में यथा परिभाषित किसी विश्वविद्यालय से है, अथवा जहां संदर्भ के अनुसार, तत्संबंध की धारा 3 के तहत इस प्रकार घोषित किए जाने वाला कोई सम विश्वविद्यालय संस्थान हो।
- (थ) “विश्वविद्यालय छात्र शिकायत निवारण समिति” (यूएसजीआरसी) से अभिप्राय विश्वविद्यालय के स्तर पर डीएसजीआरसी, आईएसजीआरसी अथवा सीएसजीआरसी के निर्णय के परिणामस्वरूप उपजी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए इन विनियमों के तहत गठित किसी समिति से है।

4. विवरणिका का अनिवार्य प्रकाशन, इसकी विषयवस्तु तथा मूल्य निर्धारण:

1. प्रत्येक संस्थान, अपने पाठ्यक्रम या अध्ययन के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश आरंभ करने की तिथि से कम से कम साठ दिन की समाप्ति से पूर्व अपनी वेबसाइट पर एक विवरणिका प्रकाशित और/अथवा अपलोड करेगा, जिसमें इस तरह के संस्थान में प्रवेश लेने के इच्छुक व्यक्तियों और आम जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् जानकारी अंतर्विष्ट होगी, नामतः:
 - (क) प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के कार्यक्रम के लिए, शिक्षण के घंटों, व्यावहारिक सत्रों और अन्य कार्य के साथ-साथ अध्ययन के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की सूची सहित उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण अथवा संस्थान, जैसा मामला हो, द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम की व्यापक रूपरेखा;
 - (ख) जिस शिक्षा वर्ष हेतु प्रवेश दिए जाने का प्रस्ताव हो, उसके प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के कार्यक्रम के संबंध में, उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या;
 - (ग) संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विशेष पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम में छात्र के रूप में प्रवेश के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा सहित शैक्षिक योग्यता और पात्रता की शर्तें;

- (घ) इस प्रकार के प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, जिसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के लिए परीक्षा या इम्तहान के विवरण के संबंध में सभी संगत जानकारी और प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क की राशि शामिल है;
- (ङ) किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में अध्ययन करने के लिए ऐसे संस्थान में भर्ती किए गए छात्रों द्वारा देय शुल्क, जमा राशियों और अन्य प्रभारों के प्रत्येक घटक और ऐसे भुगतानों की अन्य निबंधन और शर्तें;
- (च) शास्ति लगाए जाने और संग्रहण किए जाने हेतु नियम/विनियम, विनिर्दिष्ट शीर्ष अथवा श्रेणियां, लगाए जाने वाली शास्ति की न्यूनतम और अधिकतम राशि;
- (छ) ऐसे संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों द्वारा यदि पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के पूरा होने से पहले अथवा के बाद दाखिला छोड़ दिया जाता है तो छात्रों को प्रतिदाय किए जाने वाले शिक्षण शुल्क और अन्य प्रभारों का प्रतिशत, तथा समय सीमा जिसके भीतर तथा पद्धति जिससे छात्रों को ऐसा प्रतिदाय किया जाएगा;
- (ज) उनकी शैक्षिक योग्यता शिक्षण संकाय का विवरण, उनकी नियुक्ति का स्वरूप (नियमित/अभ्यागत/अतिथि) और उसके प्रत्येक सदस्य के शिक्षण अनुभव के साथ;
- (झ) भौतिक और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे और छात्रावास और इसके शुल्क, पुस्तकालय, अस्पताल अथवा उद्योग, जहां छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना हो, सहित अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी और विशेषरूप से छात्रों द्वारा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं का ब्योरा अंतर्विष्ट हो;
- (ञ) संस्थान के परिसर के भीतर अथवा बाहर छात्रों द्वारा अनुशासन बनाए रखने के संबंध में सभी संगत निदेश, और, विशेषरूप से किसी छात्र अथवा छात्रों की रैगिंग निषिद्ध करने संबंधी ऐसे अनुशासन को बनाए रखने और उनका उल्लंघन किए जाने के परिणामों और संगत सांविधिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में तैयार किए गए किसी विनियम के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के परिणामों का ब्योरा अंतर्विष्ट होगा; तथा
- (ट) आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी:

बशर्ते कि, प्रत्येक संस्थान इस विनियम के खंड (क) से (ट) में उल्लिखित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित/अपलोड करेगा, और विभिन्न समाचारपत्रों और अन्य मीडिया के माध्यम से प्रमुखता से प्रदर्शित करते हुए विज्ञापनों के माध्यम से इच्छुक छात्रों और आम जनता का ध्यान वेबसाइट पर इस तरह के प्रकाशन की ओर दिलाया जाएगा ।

2. प्रत्येक संस्थान अपनी विवरणिका की प्रत्येक मुद्रित प्रति का मूल्य निर्धारित करेगा, जोकि विवरणिका के प्रकाशन और वितरण की उचित लागत से अधिक नहीं होगी और विवरणिका के प्रकाशन, वितरण या बिक्री से कोई लाभ अर्जित नहीं किया जाएगा ।

5. छात्र शिकायत निवारण समितियां (एसजीआरसी):

क. महाविद्यालयी छात्र शिकायत निवारण समिति (सीएसजीआरसी)

- (i) किसी भी पीड़ित छात्र की महाविद्यालय से संबंधित किसी भी शिकायत को निम्नलिखित संरचना वाली महाविद्यालयी छात्र शिकायत निवारण समिति (सीएसजीआरसी) को भेजा जाएगा:
- (क) महाविद्यालय का प्राचार्य— सभापति;
- (ख) प्राचार्य द्वारा शिक्षण संकाय से तीन वरिष्ठ सदस्यगणों को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा— सदस्यगण;
- (ग) महाविद्यालय के छात्रों में से एक प्रतिनिधि, जिसे प्राचार्य द्वारा शैक्षणिक योग्यता/खेलकूद में उत्कृष्टता/सह-पाठ्य क्रियाकलापों में उसके निष्पादन के आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा— विशेष आमंत्रित ।
- (ii) सदस्यगणों तथा विशेष आमंत्रित का कार्यकाल दो वर्षों का होगा ।
- (iii) बैठक के लिए गणपूर्ति, सभापति सहित परंतु विशेष आमंत्रित के अलावा, तीन सदस्यगणों की होगी ।
- (iv) शिकायतों पर विचार करते हुए सीएसजीआरसी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी ।

- (v) सीएसजीआरसी रिपोर्ट को अपनी सिफारिशों, यदि कोई हो तो, के साथ संबद्ध करने वाले विश्वविद्यालय के कुलपति को शिकायत प्राप्त की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर भेजेगा तथा इसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को भी भेजी जाएगी।

ख. विभागीय छात्र शिकायत निवारण समिति (डीएसजीआरसी)

- (i) किसी भी पीड़ित छात्र की विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग, अथवा विद्यालय, अथवा केन्द्र से संबंधित किसी भी शिकायत को विभाग, विद्यालय अथवा केन्द्र, जैसा भी मामला हो, द्वारा गठित की जाने और निम्नलिखित संरचना वाली विभागीय छात्र शिकायत निवारण समिति (डीएसजीआरसी) को भेजा जाएगा, नामतः:
- (क) विभाग, विद्यालय, अथवा केन्द्र का अध्यक्ष, चाहे उसे किसी भी पदनाम से जाना जाए— सभापति;
- (ख) विभाग/विद्यालय/केन्द्र के बाहर से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो आचार्य— सदस्य;
- (ग) संकाय का सदस्य, जो शिकायत निवारण की प्रणाली से भली-भांति परिचित हो, को सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा— सदस्य;
- (घ) महाविद्यालय के छात्रों में से एक प्रतिनिधि, जिसे कुलपति द्वारा शैक्षणिक योग्यता/खेलकूद में उत्कृष्टता/सह-पाठ्य क्रियाकलापों में उसके निष्पादन के आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा— विशेष आमंत्रित
- (ii) सभापति, समिति के सदस्यों और विशेष आमंत्रित का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।
- (iii) डीएसजीआरसी की बैठक के लिए गणपूर्ति, सभापति सहित परंतु विशेष आमंत्रित के अलावा, तीन सदस्यगणों की होगी।
- (iv) अपने समक्ष प्रस्तुत शिकायतों पर विचार करते हुए डीएसजीआरसी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी।
- (v) डीएसजीआरसी अपनी रिपोर्ट को सिफारिशों, यदि कोई हों तो, के साथ संस्थान के मुखिया/ कुलपति को शिकायत प्राप्त की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर भेजेगा तथा इसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को भी भेजी जाएगी।

ग. संस्थागत छात्र शिकायत निवारण समिति (आईएसजीआरसी)

- (i) जब शिकायत किसी विश्वविद्यालय के किसी शैक्षणिक विभाग, विद्यालय अथवा केन्द्र, जैसा भी मामला हो, से संबद्ध नहीं हो तो मामले को कुलपति महोदय द्वारा निम्नवत संरचना के साथ गठित की जाने वाली एक संस्थागत छात्र शिकायत निवारण समिति (आईएसजीआरसी) को भेजा जाएगा; नामतः:
- (क) संस्थान का सम-कुलपति/संकाय अध्यक्ष/वरिष्ठ आचार्य— सभापति;
- (ख) छात्र संकाय अध्यक्ष/संकाय अध्यक्ष, छात्र कल्याण— सदस्य;
- (ग) सभापति के अलावा एक वरिष्ठ शिक्षाविद्— सदस्य;
- (घ) कुलानुशासक/वरिष्ठ शिक्षाविद्— सदस्य
- (ङ) महाविद्यालय के छात्रों में से एक प्रतिनिधि, जिसे कुलपति द्वारा शैक्षणिक योग्यता/खेलकूद में उत्कृष्टता/सह-पाठ्य क्रियाकलापों में उसके निष्पादन के आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा— विशेष आमंत्रित।
- (ii) समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।
- (iii) आईएसजीआरसी की बैठक के लिए गणपूर्ति, सभापति सहित परंतु विशेष आमंत्रित के अलावा, तीन सदस्यगणों की होगी।
- (iv) अपने समक्ष प्रस्तुत शिकायतों पर विचार करते हुए आईएसजीआरसी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी।
- (v) आईएसजीआरसी अपनी रिपोर्ट को सिफारिशों, यदि कोई हों तो, के साथ कुलपति को शिकायत प्राप्त की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर भेजेगा तथा इसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को भी भेजी जाएगी।

घ. विश्वविद्यालय छात्र शिकायत निवारण समिति (यूएसजीआरसी)

- (i) एक संबद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति, उतनी संख्या में विश्वविद्यालय छात्र शिकायत निवारण समितियों (यूएसजीआरसी) का गठन करेंगे, जैसा कि एक या एक से अधिक सीएसजीआरसी या डीएसजीआरसी या आईएसजीआरसी द्वारा अनसुलझी शिकायतों पर विचार करने के लिए आवश्यक हो और प्रत्येक यूएसजीआरसी, महाविद्यालयों/विभागों/संस्थानों से उत्पन्न होने वाली शिकायतों पर, कुलपति द्वारा उसे प्रदत्त किए गए क्षेत्राधिकार क्षेत्र के आधार पर कार्यवाही कर सकता है।
 - क) विश्वविद्यालय का एक वरिष्ठ आचार्य— सभापति;
 - ख) संकाय अध्यक्ष, छात्र कल्याण अथवा समकक्ष – सदस्य;
 - ग) संबद्ध महाविद्यालयों से लिए गए दो प्राचार्य, जो कि समीक्षाधीन सीएसजीआरसी की रिपोर्टों से न जुड़े हों, कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले हैं— सदस्य;
 - घ) विश्वविद्यालय का एक आचार्य – सदस्य;
 - ङ) महाविद्यालय के छात्रों में से एक प्रतिनिधि, जिसे कुलपति द्वारा शैक्षणिक योग्यता/खेलकूद में उत्कृष्टता/सह-पाठ्य क्रियाकलापों में उसके निष्पादन के आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा— विशेष आमंत्रित।
- (ii) सभापति तथा समिति के सदस्यों और विशेष आमंत्रित का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।
- (iii) बैठक के लिए गणपूर्ति, सभापति सहित परंतु विशेष आमंत्रित के अलावा, तीन सदस्यगणों की होगी।
- (iv) अपने समक्ष शिकायतों पर विचार करते हुए यूएसजीआरसी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी।
- (v) यूएसजीआरसी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें, यदि कोई हों तो, के साथ शिकायत से संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/विद्यालय/संस्थान को शिकायत प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर भेजेगी तथा इसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को भी भेजी जाएगी।
- (vi) विश्वविद्यालय छात्र शिकायत निवारण समिति के निर्णय से व्यथित कोई भी छात्र, इस तरह के निर्णय की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है।

6. लोकपाल की नियुक्ति, सेवाकाल, उसे पद से हटाया जाना और सेवा की शर्तें:

- (i) यूएसजीआरसी के निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई करने और निर्णय देने और अपील करने के लिए एक या एक से अधिक अंशकालिक पदाधिकारियों को लोकपाल के रूप में नामित किया जाएगा;

बशर्ते कि, उस राज्य में स्थित सभी राज्य विश्वविद्यालयों (सार्वजनिक के साथ— साथ निजी विश्वविद्यालयों) के संबंध में एक राज्य के लिए एक से अधिक लोकपाल नहीं होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

बशर्ते आगे कि, एक क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालय संस्थानों के लिए एक से अधिक लोकपाल नहीं होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (ii) लोकपाल, शिक्षा अथवा अनुसंधान के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति होंगे, जो किसी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हों।
- (iii) किसी राज्य में राज्य विश्वविद्यालयों के लिए लोकपाल, उस राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय के साथ हितों के टकराव में नहीं होगा; और उस क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों हेतु लोकपाल, इस तरह की नियुक्ति से पहले अथवा उसके पश्चात्, उस क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय अथवा सम विश्वविद्यालय संस्थान के साथ किसी भी तरह के हितों के टकराव में नहीं होंगे।
- (iv) एक राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ गठित एक खोज समिति द्वारा सुझाए गए तीन नामों के पैनल में से लोकपाल की नियुक्ति करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, नामतः
 - (क) राज्यपाल या उपराज्यपाल का एक नामित, जैसा भी मामला हो, जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो— सभापति;
 - (ख) राज्य के राज्यपाल/संघ भासित राज्य के उपराज्यपाल द्वारा नामित किया जाने वाला राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय का कुलपति— सदस्य;

- (ग) राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला एक राज्य निजी विश्वविद्यालय का कुलपति— सदस्य;
- (घ) राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् का अध्यक्ष अथवा परिषद् के शैक्षणिक सदस्यों में से उनका नामिति— सदस्य;
- (ङ) उच्चतर शिक्षा के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार के प्रधान सचिव/सचिव— सदस्य सचिव;
- (v) केंद्र सरकार इस प्रयोजनार्थ गठित एक खोज समिति द्वारा सुझाए गए तीन नामों के पैनल में से लोकपाल की नियुक्ति करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, नामतः
- (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय अथवा उनके नामिति— सभापति;
- (ख) किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा— सदस्य;
- (ग) किसी सम विश्वविद्यालय संस्थान का कुलपति जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए— सदस्य;
- (घ) केन्द्र सरकार का नामिति जोकि संयुक्त सचिव के पद से नीचे न हो— सदस्य;
- (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव महोदय— सदस्य सचिव;
- (vi) लोकपाल को पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा सत्तर वर्ष की आयु होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाएगा, और वह समान राज्य या क्षेत्र के लिए, जैसा कि मामला हो, एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति होने के लिए पात्र होगा।
- (vii) सुनवाई का संचालन करने के लिए, लोकपाल को, यात्रा पर हुए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार, प्रति दिन, प्रति बैठक के आधार पर शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- (viii) राज्य के लोकपाल के मामले में राज्य सरकार द्वारा और किसी क्षेत्र के लोकपाल के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल को इन विनियमों के तहत यथा परिभाषित कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोप सिद्ध होने पर पद से हटाया जा सकता है।
- (ix) कम से कम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर आसीन न्यायमूर्ति द्वारा की गई जांच के अलावा लोकपाल को पदच्युत करने हेतु कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा, और इस प्रकार की गई जांच में लोकपाल को सुनवाई का एक उचित अवसर भी प्रदान किया जाएगा।

7. लोकपाल के कार्यकरण :

- (i) लोकपाल, छात्र द्वारा इन विनियमों के तहत उपबंधित सभी विकल्पों को अपनाने के पश्चात् ही पीड़ित छात्र की अपील की सुनवाई करेंगे।
- (ii) यद्यपि, परीक्षा के संचालन में अथवा मूल्यांकन की प्रक्रिया में गड़बड़ी के मुद्दों को लोकपाल के संदर्भित किया जा सकता है, तथापि, लोकपाल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन अथवा अंकों को पुनः योग करने हेतु कोई अपील अथवा आवेदन पर लोकपाल द्वारा सुनवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि भेदभाव की किसी विशिष्ट घटना के परिणामों को प्रभावित करने वाली किसी विशिष्ट अनियमितता को इंगित नहीं किया जाता है।
- (iii) लोकपाल, कथित रूप से किए गए भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए, न्याय— मित्र के रूप में किसी भी व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सकता है।
- (iv) लोकपाल पीड़ित छात्र(त्रों) से अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान के लिए सभी प्रयास करेगा।

8. लोकपाल तथा छात्र शिकायत निवारण समितियों द्वारा शिकायतों के निवारण हेतु प्रक्रिया:

- (i) प्रत्येक संस्थान, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगा, जहां कोई भी पीड़ित छात्र अपनी शिकायत के निवारण के लिए आवेदन कर सकता है।
- (ii) ऑनलाइन शिकायत प्राप्त होने पर संस्थान, ऑनलाइन शिकायत की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियों सहित शिकायत को उपर्युक्त छात्र शिकायत निवारण समिति को भेजेगा।

- (iii) छात्र शिकायत निवारण समिति, जैसा भी मामला हो, शिकायत की सुनवाई के लिए एक तिथि निर्धारित करेगी जिसकी जानकारी संस्थान और पीड़ित छात्र को दी जाएगी।
- (iv) पीड़ित छात्र या तो व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकता है अथवा अपना पक्ष रखने के लिए अपने किसी प्रतिनिधि को अधिकृत कर सकता है।
- (v) विश्वविद्यालय छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा समाधान नहीं की गई शिकायतों, को इन विनियमों में उपबंधित समयावधि के भीतर लोकपाल को भेजा जाएगा।
- (vi) संस्थान, शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु, लोकपाल अथवा छात्र शिकायत निवारण समिति(यों), जैसा भी मामला हो, सहयोग करेंगे; और ऐसा नहीं किए जाने पर लोकपाल द्वारा आयोग को जानकारी दी जा सकती है जो इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप कार्रवाई करेगा।
- (vii) लोकपाल, दोनों पक्षों को सुने जाने का एक उचित अवसर प्रदान करने के बाद, कार्यवाहियां समाप्त होने पर तत्संबंधी कारणों सहित, इस प्रकार का आदेश पारित करेगा, जैसा वह उपयुक्त समझे, ताकि शिकायत का समाधान हो सके और पीड़ित छात्र को जैसा उपयुक्त हो, राहत प्रदान की जा सके।
- (viii) संस्थान के साथ ही साथ पीड़ित छात्र को लोकपाल के हस्ताक्षर के तहत जारी की गई आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी और संस्थान, आदेश की प्रति को सामान्य जानकारी के लिए इसे अपनी वेबसाइट पर भी डालेगा।
- (ix) संस्थान, लोकपाल की सिफारिशों का अनुपालन करेगा और संस्थान द्वारा सिफारिशों का अनुपालन नहीं किए जाने के संबंध में लोकपाल, आयोग को जानकारी प्रदान करेगा।
- (x) जहां शिकायत झूठी या तुच्छ पाई जाती है उस स्थिति में लोकपाल शिकायतकर्ता के विरुद्ध उपर्युक्त कार्रवाई किए जाने की सिफारिश कर सकता है।

9. लोकपाल और छात्र शिकायत निवारण समितियों के संबंध में जानकारी:

संस्थान अपनी वेबसाइट और अपनी विवरणिका में स्पष्टरूप से इसके क्षेत्राधिकार में आने वाली छात्र शिकायत निवारण समिति(यों) तथा अपील किए जाने के प्रयोजनार्थ लोकपाल के संबंध में सभी संगत जानकारियां उपलब्ध कराएगा।

10. अनुपालन नहीं किए जाने के परिणाम:

आयोग, किसी भी संस्थान के संबंध में, जो जानबूझकर इन विनियमों का उल्लंघन करते हैं अथवा बार- बार लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति(यों), जैसा भी मामला हो, की सिफारिशों को अनुपालन नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध निम्नवत् एक अथवा एक से अधिक कार्यवाहियां कर सकते हैं, नामतः:

- (क) अधिनियम की धारा 12ख के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता की घोषणा को वापस लेना;
- (ख) संस्थान को आवंटित किसी भी अनुदान को रोका जा सकता है;
- (ग) आयोग के किसी भी सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत किसी भी सहायता को प्राप्त करने हेतु विचार किए जाने के लिए संस्थान को अयोग्य घोषित करना;
- (घ) उपयुक्त मीडिया में प्रमुखता से प्रदर्शित कर और आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट कर संभावित अभ्यर्थियों सहित जनसाधारण को सूचित करना, तथा इस बाबत घोषणा करना की संस्थान में शिकायतों के निवारण के लिए न्यूनतम मानक मौजूद नहीं हैं;
- (ङ) महाविद्यालय के मामले में, संबद्धता को वापस लेने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय को सिफारिश करना;
- (च) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में इस प्रकार की कार्रवाई करना, जो आवश्यक, उपयुक्त और सटीक प्रतीत हो;
- (छ) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषणा को वापस लिया जाने के लिए, यदि आवश्यक हो तो, केंद्र सरकार को सिफारिश करना;
- (ज) राज्य अधिनियम के तहत स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय के मामले में राज्य सरकार को आवश्यक और उचित कार्रवाई करने की सिफारिश करना;
- (झ) गैर-अनुपालन के लिए संस्थान के विरुद्ध ऐसी अन्य कार्रवाई करना जो आवश्यक और उचित समझी जाए।

बशर्ते कि, इस विनियमों के तहत आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि संस्थान को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अवसर नहीं दिया गया हो और उसे सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

11. इन विनियमों में उल्लिखित कोई भी शर्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 के उपबंधों के तहत नियुक्त किसी पदधारी लोकपाल के कार्यकाल की अवधि के दौरान उसके पद पर बने रहने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी; कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् लोकपाल, की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) संबंधी विनियम, 2019 के अनुरूप की जाएगी।

प्रो. रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 30 / 19]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2019

F.No. 14-4/2012(CPP-II).—In exercise of the powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the University Grants Commission (Grievance Redressal) Regulations, 2012, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely -

1. SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT:

- These regulations shall be called as the University Grants Commission (Redress of Grievances of Students) Regulations, 2019.
- They shall apply to all higher education institutions, whether established or incorporated by or under a Central Act or a State Act, and every institution recognized by the University Grants Commission under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and to all institutions deemed to be a University declared as such under Section 3 therein.
- They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. OBJECTIVE:

To provide opportunities for redress of certain grievances of students already enrolled in any institution, as well as those seeking admission to such institutions, and a mechanism thereto.

3. DEFINITION: IN THESE REGULATIONS, UNLESS THE CONTEXT OTHERWISE REQUIRES:

- “Act” means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- “aggrieved student” means a student, who has any complaint in the matters relating to or connected with the grievances defined under these regulations.
- “college” means any institution, so defined in clause (b) of sub-section (1) of section 12A of the Act.
- “Collegiate Student Grievance Redressal Committee” (CSGRC) means a committee constituted under these regulations, at the level of an institution, being a college.
- “Commission” means the University Grants Commission established under section 4 of the UGC Act, 1956.
- “declared admission policy” means such policy, including the process there under, for admission to a course or program of study as may be offered by the institution by publication in the prospectus of the institution.
- “Departmental Student Grievance Redressal Committee” (DSGRC) means a committee constituted under these regulations, at the level of a Department, School or Centre of a University.
- “grievance” means, and includes, complaint(s) made by an aggrieved student in respect of the following, namely:

- i. admission contrary to merit determined in accordance with the declared admission policy of the institution;
 - ii. irregularity in the process under the declared admission policy of the institution;
 - iii. refusal to admit in accordance with the declared admission policy of the institution;
 - iv. non-publication of prospectus by the institution, in accordance with the provisions of these regulations;
 - v. publication by the institution of any information in the prospectus, which is false or misleading, and not based on facts;
 - vi. withholding of, or refusal to return, any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited by a student for the purpose of seeking admission in such institution, with a view to induce or compel such student to pay any fee or fees in respect of any course or program of study which such student does not intend to pursue;
 - vii. demand of money in excess of that specified to be charged in the declared admission policy of the institution;
 - viii. violation, by the institution, of any law for the time being in force in regard to reservation of seats in admission to different category of students;
 - ix. nonpayment or delay in payment of scholarships or financial aid admissible to any student under the declared admission policy of such institution, or under the conditions, if any, prescribed by the Commission;
 - x. delay by the institution in the conduct of examinations, or declaration of results, beyond the schedule specified in the academic calendar of the institution, or in such calendar prescribed by the Commission;
 - xi. failure by the institution to provide student amenities as set out in the prospectus, or is required to be extended by the institution under any provisions of law for the time being in force;
 - xii. non-transparent or unfair practices adopted by the institution for the evaluation of students;
 - xiii. delay in, or denial of, the refund of fees due to a student who withdraws admission within the time mentioned in the prospectus, or as may be notified by the Commission;
 - xiv. complaints of alleged discrimination of students from the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Women, Minority or persons with disabilities categories;
 - xv. denial of quality education as promised at the time of admission or required to be provided; and
 - xvi. harassment or victimization of a student, other than cases of harassment, which are to be proceeded against under the penal provisions of any law for the time being in force.
- (i) “Institution” means, as the context may be, a University or a college, or an institution declared a deemed to be a University under the Act or an institution established within a University for a particular discipline or activity;
- (j) Institutional Student Grievance Redressal Committee” (ISGRC) means a committee constituted under these regulations at the level of the University, for dealing with grievances which do not belong to a department of the University e.g. hostels and common facilities.
- (k) “Ombudsperson” means the Ombudsperson appointed under these regulations;
- (l) “Prospectus” means and includes any publication, whether in print or otherwise, issued for providing fair and transparent information, relating to an institution, to the general public (including to those seeking admission in such institution) by such institution or any authority or person authorized by such institution to do so;

- (m) "Region" means a geographical territory, comprising of States, so determined, for the purpose of facilitating enforcement of these regulations; namely, South-Eastern Region comprising Andhra Pradesh, Telengana, Puducherry, Andaman and Nicobar, and Tamil Nadu; South-Western Region comprising Kerala, Karnataka, and Lakshadweep; Western Region comprising Maharashtra, Gujarat, Goa, Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu; Central Region comprising Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan; Northern Region comprising Jammu and Kashmir, Delhi, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Chandigarh; North-Eastern Region comprising Assam, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh, Sikkim and Nagaland; and Eastern Region comprising West Bengal, Bihar, Jharkhand and Odisha.
- (n) "State" means a State specified in the First Schedule to the Constitution and includes a Union territory;
- (o) "Student" means a person enrolled, or seeking admission to be enrolled, in any institution to which these regulations apply;
- (p) "University" means a University so defined in clause (f) of section 2 of the Act or, where the context may be, an institution deemed to be University declared as such under Section 3 thereof.
- (q) "University Student Grievance Redressal Committee" (USGRC) means a committee constituted under these regulations, at the level of the university, for dealing with grievances arising out of decisions of the DSGRC, ISGRC or CSGRC.

4. MANDATORY PUBLICATION OF PROSPECTUS, ITS CONTENTS AND PRICING:

- (1) Every institution, shall publish and/or upload on its website, before expiry of at least sixty days prior to the date of the commencement of the admission to any of its courses or programs of study, a prospectus containing the following for the information of persons intending to seek admission to such institution and the general public, namely:
- the list of programs of study and courses offered along with the broad outlines of the syllabus specified by the appropriate statutory authority or by the institution, as the case may be, for every course or program of study, including teaching hours, practical sessions and other assignments;
 - the number of seats approved by the appropriate statutory authority in respect of each course or program of study for the academic year for which admission is proposed to be made;
 - the conditions of educational qualifications and eligibility including the minimum and maximum age limit of persons for admission as a student in a particular course or program of study, specified by the institution;
 - the process of selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course or program of study and the amount of fee prescribed for the admission test;
 - each component of the fee, deposits and other charges payable by the students admitted to such institution for pursuing a course or program of study, and the other terms and conditions of such payment;
 - rules/regulations for imposition and collection of any fines in specified heads or categories, minimum and maximum fine may be imposed.
 - the percentage of tuition fee and other charges refundable to a student admitted in such institution in case such student withdraws from such institution before or after completion of course or program of study and the time within and the manner in which such refund shall be made to that student;
 - details of the teaching faculty, including their educational qualifications, along with their type of appointment (Regular/visiting/guest) and teaching experience of every member thereof.
 - information with regard to physical and academic infrastructure and other facilities including hostel accommodation and its fee, library, hospital or industry wherein the practical training is

to be imparted to the students and in particular the amenities accessible by students on being admitted to the institution;

- (j) all relevant instructions in regard to maintaining the discipline by students within or outside the campus of the institution, and, in particular such discipline relating to the prohibition of ragging of any student or students and the consequences thereof and for violating the provisions of any regulation in this behalf made by the relevant statutory regulatory authority; and
- (k) Any other information as may be specified by the Commission:

Provided that an institution shall publish/upload information referred to in clauses (a) to (k) of this regulation, on its website, and the attention of prospective students and the general public shall be drawn to such publication being on the website through advertisements displayed prominently in different newspapers and through other media:

- (2) Every institution shall fix the price of each printed copy of the prospectus, being not more than the reasonable cost of its publication and distribution and no profit be made out of the publication, distribution or sale of prospectus.

5. **STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES (SGRC):**

A. Collegiate Student Grievance Redressal Committee (CSGRC)

- (i) A complaint from an aggrieved student relating to a college shall be addressed to the Collegiate Student Grievance Redressal Committee (CSGRC), with the following composition, namely:
 - a) Principal of the college – Chairperson;
 - b) Three senior members of the teaching faculty to be nominated by the Principal – Members;
 - c) A representative from among students of the college to be nominated by the Principal based on academic merit/excellence in sports/performance in co-curricular activities – Special Invitee.
- (ii) The term of the members and the special invitee shall be two years.
- (iii) The quorum for the meeting including the Chairperson, but excluding the special invitee, shall be three.
- (iv) In considering the grievances before it, the CSGRC shall follow principles of natural justice.
- (v) The CSGRC shall send its report with recommendations, if any, to the Vice-Chancellor of the affiliating University and a copy thereof to the aggrieved student, within a period of 15 days from the date of receipt of the complaint.

B. Departmental Student Grievance Redressal Committee (DSGRC)

- (i) A complaint by an aggrieved student relating to a Department, or School, or Centre of a University shall be addressed to the Departmental Student Grievance Redressal Committee (DSGRC) to be constituted at the level of the Department, School, or Centre, as the case may be, and with the following composition, namely:
 - a) Head of the Department, School, or the Centre, by whatever designation known – Chairperson;
 - b) Two Professors, from outside the Department/School/Centre to be nominated by the Vice Chancellor – Members;
 - c) A member of the faculty, well-versed with the mechanism of grievance redressal to be nominated by the Chairperson – Member;
 - d) A representative from among students of the college to be nominated by the Vice Chancellor based on academic merit/excellence in sports/performance in co-curricular activities – Special Invitee.

- (ii) The term of the Chairperson, members of the Committee, and the special invitee shall be of two years.
- (iii) The quorum for the meeting of DSGRC, including the Chairperson, but excluding the special invitee, shall be three.
- (iv) In considering the grievances before it, the DSGRC shall follow principles of natural justice.
- (v) The DSGRC shall submit its report with recommendations, if any, to the Head of the Institution/ Vice Chancellor, with a copy thereof to the aggrieved student, within a period of 15 days from the date of receipt of the complaint.

C. Institutional Student Grievance Redressal Committee (ISGRC)

- (i) Where a complaint does not relate to any academic Department, School or Centre of a University, as the case may be, the matter shall be referred to the Institutional Student Grievance Redressal Committee (ISGRC) to be constituted by the Vice Chancellor, with the following composition, namely:
 - (a) Pro-Vice Chancellor/Dean/Senior Professor of institution – Chairperson;
 - (b) Dean of students/Dean, Students Welfare – Member;
 - (c) One senior academic, other than the Chairperson – Member;
 - (d) Proctor/Senior academic – Member;
 - (e) A representative from among students of the college to be nominated by the Vice Chancellor based on academic merit/excellence in sports/performance in co-curricular activities – Special Invitee.
- (ii) The term of the members of the committee shall be of two years.
- (iii) The quorum for the meetings of the ISGRC, including the Chairperson, but excluding the special invitee, shall be three.
- (iv) In considering the grievances before it, the ISGRC shall follow principles of natural justice.
- (v) The ISGRC shall send its report with recommendations, if any, to the Vice Chancellor, along with a copy thereof to the aggrieved student, within a period of 15 workings days from the date of receipt of the grievance.

D. University Student Grievance Redressal Committee (USGRC)

- (i) The Vice Chancellor of an affiliating University shall constitute such number of University Student Grievance Redressal Committees (USGRC), as may be required to consider grievances unresolved by one or more CSGRC or DSGRC or ISGRC and each USGRC may take up grievances arising from colleges/departments/ Institutions, on the basis of the jurisdiction assigned to it by the Vice Chancellor.
 - a) A senior Professor of the University – Chairperson;
 - b) Dean, Student Welfare or equivalent – Member;
 - c) Two Principals drawn from the affiliating colleges, other than those connected with reports of CSGRC under review, to be nominated by the Vice-Chancellor – Members;
 - d) One Professor of the University - Member;
 - e) A representative from among students of the college to be nominated by the Vice Chancellor based on academic merit/excellence in sports/performance in co-curricular activities – Special Invitee.
- (ii) The Chairperson, members and the special invitee shall have a term of two years.
- (iii) The quorum for the meeting, including the Chairperson, but excluding the special invitee, shall be three.

- (iv) In considering the grievances before it, the USGRC shall follow principles of natural justice.
- (v) The USGRC shall send its report and recommendations, if any, to the Principal of the College relating to the grievance/Head of the department/School/Institution with a copy thereof to the aggrieved student, within 15 days of the receipt of the grievance.
- (vi) Any student aggrieved by the decision of the University Student Grievance Redressal Committee may prefer an appeal to the Ombudsperson, within in a period of fifteen days from the date of receipt of such decision.

6. APPOINTMENT, TENURE, REMOVAL AND CONDITIONS OF SERVICES OF OMBUDSPERSON:

- (i) There shall be one or more part-time functionaries designated as Ombudspersons to hear, and decide on, appeals preferred against the decisions of the USGRCs.

Provided that, there shall not be more than one ombudsperson for a State, in respect of all the State universities (Public as well as Private) in that State, who shall be appointed by the State Government;

Provided further that, there shall not be more than one Ombudsperson for a region, in respect of the Central universities and institutions deemed to be universities in that region, who shall be appointed by the Central Government.

- (ii) The Ombudsperson shall be a person of eminence in academics or research, who had been Vice-Chancellor of a University.
- (iii) The Ombudsperson for the State universities in a State, shall not be in any conflict of interest with any University in that State; and the Ombudsperson for the Central universities and institutions deemed to be universities in a region, shall not be in any conflict of interest with any University or institution deemed to be University in that region, either before or after such appointment.
- (iv) A State Government shall appoint the Ombudsperson from a panel of three names recommended by a search committee constituted for that purpose and consisting of the following, namely:
 - (a) A nominee of the Governor or Lt. Governor, as the case may be, who is a person of eminence in the field of higher education— Chairperson;
 - (b) A Vice Chancellor from a State Public University to be nominated by the Governor/LG of the State/UT - Member;
 - (c) A Vice Chancellor from a State Private University to be nominated by the State Government – Member;
 - (d) Chairperson of the State Council of Higher Education or his/her nominee from among the academic members of the Council— Member;
 - (e) Principal Secretary/Secretary to the State Government responsible for Higher Education— Member Secretary.
- (v) The Central Government shall appoint the Ombudsperson for a region from a panel of three names recommended by a search committee to be constituted for that purpose, and consisting of the following, namely:
 - (a) Chairperson, University Grants Commission or his/her nominee – Chairperson
 - (b) A Vice Chancellor of a Central University to be nominated by the Central Government – Member
 - (c) A Vice Chancellor of an institution deemed to be University to be nominated by the Central Government – Member
 - (d) A nominee of the Central Government, not below the rank of the Joint Secretary – Member
 - (e) Secretary, University Grants Commission – Member Secretary

- (vi) The Ombudsperson shall be appointed for a period of three years or until he attains the age of 70 years, whichever is earlier, from the date of assuming office, and shall be eligible for reappointment for another one term for the same State or region, as the case may be.
- (vii) For conducting the hearings, the Ombudsperson shall be paid a sitting fee, per diem, in accordance with the norms fixed by the University Grants Commission, and shall, in addition, be eligible for reimbursement of the expenditure incurred on conveyance.
- (viii) The State Government, in the case of an Ombudsperson of a State, and the Central Government, in the case of an Ombudsperson of a region, may remove the Ombudsperson from office, on charges of proven misconduct or misbehavior as defined under these regulations.
- (ix) No order of removal of Ombudsperson shall be made except after an inquiry made in this regard by a person not below the rank of judge of the High Court in which a reasonable opportunity of being heard is given to the Ombudsperson.

7. FUNCTIONS OF OMBUDSPERSON:

- (i) The Ombudsperson shall hear appeals from an aggrieved student, only after the student has availed all other remedies provided under these regulations.
- (ii) While issues of malpractices in the conduct of examination or in the process of evaluation may be referred to the Ombudsperson, no appeal or application for revaluation or re-totaling of answer sheets from an examination, shall be entertained by the Ombudsperson unless specific irregularity materially affecting the outcome of specific instance of discrimination is indicated.
- (iii) The Ombudsperson may avail assistance of any person, as amicus curiae, for hearing complaints of alleged discrimination.
- (iv) The Ombudsperson shall make all efforts to resolve the grievances within a period of 30 days of receiving the appeal from the aggrieved student(s).

8. PROCEDURE FOR REDRESSAL OF GRIEVANCES BY OMBUDSPERSONS AND STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES:

- (i) Each institution shall, within a period of three months from the date of issue of this notification, have an online portal where any aggrieved student may submit an application seeking redressal of grievance.
- (ii) On receipt of an online complaint, the institution shall refer the complaint to the appropriate Student Grievance Redressal Committee, along with its comments within 15 days of receipt of complaint on the online portal.
- (iii) The Student Grievance Redressal Committee, as the case may be, shall fix a date for hearing the complaint which shall be communicated to the institution and the aggrieved student.
- (iv) An aggrieved student may appear either in person or authorize a representative to present the case.
- (v) Grievances not resolved by the University Student Grievance Redressal Committee shall be referred to the Ombudsperson, within the time period provided in these regulations.
- (vi) Institutions shall extend co-operation to the Ombudsperson or the Student Grievance Redressal Committee(s), as the case may be, in early redressal of grievances; and failure to do so may be reported by the Ombudsperson to the Commission, which shall take action in accordance with the provisions of these regulations.
- (vii) The Ombudsperson shall, after giving reasonable opportunities of being heard to both parties, on the conclusion of proceedings, pass such order, with reasons there for, as may be deemed fit to redress the grievance and provide such relief as may be appropriate to the aggrieved student.
- (viii) The institution, as well as the aggrieved student, shall be provided with copies of the order under the signature of the Ombudsperson, and the institution shall place it for general information on its website.

- (ix) The institution shall comply with the recommendations of the Ombudsperson; and the Ombudsperson shall report to the Commission any failure on the part of the institution to comply with the recommendations.
- (x) The Ombudsperson may recommend appropriate action against the complainant, where a complaint is found to be false or frivolous.

9. INFORMATION REGARDING OMBUDSPERSONS AND STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES:

An institution shall furnish, prominently, on its website and in its prospectus, all relevant information in respect of the Student Grievance Redressal Committee(s) coming in its purview, and the Ombudsperson for the purpose of appeals.

10. CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE:

The Commission shall in respect of any institution, which willfully contravenes these regulations or repeatedly fails to comply with the recommendation of the Ombudsperson or the Grievance Redressal Committee(s), as the case may be, proceed to take one or more of the following actions, namely:

- (a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act;
- (b) withholding any grant allocated to the Institution;
- (c) declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programs of the Commission;
- (d) informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not possess the minimum standards for redressal of grievances;
- (e) recommend to the affiliating University for withdrawal of affiliation, in case of a college;
- (f) take such action as it may deem necessary, appropriate and fit, in case of an institution deemed to be University;
- (g) recommend to the Central Government, if required, for withdrawal of declaration as institution deemed to be a University, in case of an institution deemed to be University;
- (h) recommend to the State Government to take necessary and appropriate action, in case of a University established or incorporated under a State Act;
- (i) such other action as may be deemed necessary and appropriate against an institution for non-compliance.

Provided that no action shall be taken by the Commission under this regulation, unless the institution has been given an opportunity to explain its position and an opportunity of being heard has been provided to it.

- 11.** Nothing mentioned hereinabove in these regulations shall affect the continuance in office, during the currency of the term, of an incumbent Ombudsperson appointed under the provisions of the UGC (Grievance Redressal) Regulations, 2012; where after, the appointment of Ombudsperson shall be made as per University Grants Commission (Redress of Grievances of Students) Regulations, 2019.

Prof. RAJNISH JAIN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./30/19]



प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23236288/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in

F.No. 14-4/2012(CPP-II)

7th December, 2018

PUBLIC NOTICE

ON

UGC (GRIEVANCE REDRESSAL) REGULATIONS, 2018

UGC had notified UGC (Grievance Redressal) Regulations, 2012 in official Gazette of India on **23rd March, 2013**. These regulations were aimed at addressing and effectively resolving grievances of students related to Higher Educational Institutions.

The UGC had received a number of responses on these regulations and hence constituted an Expert Committee to revisit UGC (Grievance Redressal) Regulations, 2012. The draft University Grants Commission (Grievance Redressal of Students) Regulations, 2018 prepared by the Committee is attached herewith for observations and suggestions of stakeholders. The feedback and comments on the above draft may be sent to UGC via email grmhei.2018@gmail.com on or before **31st December, 2018**.

(Prof. Rajnish Jain)

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI – 110 002**

NOTIFICATION

F.No.14-4/2012 (CPP-II)

New Delhi, the __ October, 2018

In exercise of the power conferred under clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the University Grants Commission (Grievance Redressal) Regulations, 2012, the University Grants Commission hereby makes the following regulations:

1. SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT:

- a) These regulations shall be called as the University Grants Commission (Grievance Redressal of Students) Regulations, 2018.
- b) They shall apply to all HEIs, whether established or incorporated by or under a Central Act or a State Act, and every institution recognised by the University Grants Commission under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and to all institutions deemed to be a university declared as such under Section 3 of the said Act.
- c) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. DEFINITION: IN THESE REGULATIONS, UNLESS THE CONTEXT OTHERWISE REQUIRES:

- (a) "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (b) "aggrieved student" means a student who has any complaint in the matters concerned with the grievances defined under these regulations, and includes a person seeking admission to any institution of higher education;
- (c) "college" means any institution, whether known as such or by any other name, which provides for a course of study for obtaining any

qualification from a university and which, in accordance with the rules and regulations of such university, is recognised as competent to provide for such course of study and present students undergoing such course of study for the examination for the award of such qualification;

(d) "Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the UGC Act, 1956.

(e) "declared admission policy" means such policy for admission to a course or program of study as may be offered by the institution and published in the prospectus referred to in sub-regulation (1) of regulation 3;

(f) "grievances" include the following complaints of the aggrieved students, namely:

- i. making admission contrary to merit determined in accordance with the declared admission policy of the institution;
- ii. irregularity in the admission process adopted by the institution;
- iii. refusing admission in accordance with the declared admission policy of the institution;
- iv. non publication of prospectus, (either hard copy / online) as specified in these regulations;
- v. publishing any information in the prospectus, which is false or misleading, and not based on facts;
- vi. withhold or refuse to return any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited with it by a students for the purpose of seeking admission in such institution, with a view to induce or compel such student to pay any fee or fees in respect of any course or program of study which such student does not intend to pursue;
- vii. demand of money in excess of that specified in the declared admission policy to be charged by such institution;

- viii. breach in reservation policy in admission as may be applicable;
 - ix. nonpayment or delay in payment of scholarships to any student that such institution is committed, under the conditions imposed by University Grants Commission, or by any other authority;
 - x. delay in conduct of examinations or declaration of results beyond the specified schedule in the academic calendar;
 - xi. on provision of student amenities as may have been promised or required to be provided by the institution;
 - xii. non transparent or unfair evaluation practices;
 - xiii. Refund of fees, in case a student withdraws the admission within the stipulated time as mentioned in the prospectus, as notified by the Commission from time to time.
- (g) "Department Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of a Department.
- (h) "Institutional Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of an Institution.
- (i) "College Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of a college.
- (j) "University Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of a University.
- (k) "Higher Educational Institution" means a University within the meaning of clause (f) of Section 2, a college within the meaning of clause (b) of sub-section (1) of Section 12A, and an institution deemed to be a University declared under Section 3, of the University Grants Commission Act, 1956;
- (l) "Institution" for the purposes of these regulations, means any university, college or such other institutions, as the case may be;
- (m) "Office of profit" means an office which is capable of yielding a profit or pecuniary gain, and to which some pay, salary, emolument, remuneration or non-compensatory allowance is attached;

(n) "Ombudsperson" means the Ombudsperson appointed under these regulations;

(o) "University" means a university established or incorporated by or under a Central Act or a State Act and includes an institution deemed to be university declared as such under Section 3 of the Act.

3. MANDATORY PUBLICATION OF PROSPECTUS, ITS CONTENTS AND PRICING:

i. Every higher educational institution, shall publish and/or upload on its website, before expiry of at least sixty days prior to the date of the commencement of the admission to any of its courses or programs of study, a prospectus containing the following for the information of persons intending to seek admission to such institution and the general public, namely:

(a) the list of programs of study and courses offered along with the broad outlines of the syllabus specified by the appropriate statutory authority or by the institution, as the case may be, for every course or program of study, including teaching hours, practical sessions and other assignments;

(b) the number of seats approved by the appropriate statutory authority in respect of each course or program of study for the academic year for which admission is proposed to be made;

(c) the conditions of educational qualifications and eligibility including the minimum and maximum age limit of persons for admission as a student in a particular course or program of study, specified by the institution;

(d) the process of selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course or program of study and the amount of fee prescribed for the admission test;

- (e) each component of the fee, deposits and other charges payable by the students admitted to such institution for pursuing a course or program of study, and the other terms and conditions of such payment;
- (f) rules / regulations for imposition and collection of any fines specified heads or categories, minimum and maximum fine may be imposed.
- (g) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a student admitted in such institution in case such student withdraws from such institution before or after completion of course or program of study and the time within and the manner in which such refund shall be made to that student;
- (h) details of the teaching faculty, including their educational qualifications, alongwith the category they belong to Regular / visiting ---- and teaching experience of every member of its teaching faculty.
- (i) information with regard to physical and academic infrastructure and other facilities including hostel accommodation and its fee, library, hospital or industry wherein the practical training to be imparted to the students and in particular the facilities accessible by students on being admitted to the institution;
- (j) all relevant instructions in regard to maintaining the discipline by students within or outside the campus of the institution.
- (k) any other information as may be specified by the Commission:

Provided that an institution shall publish / upload information referred to in items (a) to (k) of this regulation, on its website, and the attention of prospective students and the general public shall be drawn to such publication on the website through advertisements displayed prominently in different newspapers and through other media:

- ii. Every institution shall fix the price of each printed copy of the prospectus, being not more than the reasonable cost of its

publication and distribution and no profit be made out of the publication, distribution or sale of prospectus.

4. GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES (GRC):

A. Department Grievance Redressal Committee (DGRC)

- (i) In case of universities, all complaints relating to a department shall first be addressed to Department Grievance Redressal Committee (DGRC) to be constituted at the level of departments/school/center whose composition shall be as follows:
 - a) Head of the Department / School / Center – Chairperson
 - b) a Professor from outside the department / school / center to be nominated by the Head of HEI – Member
 - c) A faculty member well-versed with grievance redressal mechanism to be nominated by the Head of the Department – Member.
- (ii) The Chairperson and members of the committee shall have a term of two years.
- (iii) The quorum for the meeting shall be two, including Chairperson.
- (iv) The DGRC shall follow the principles of natural justice while deciding the grievances of the students.
- (v) The DGRC shall make efforts to resolve the grievance within the stipulated period and shall submit its report to the Head of the Institution within a period of 15 days from the date of receipt of complaint to the DGRC.
- (vi) The DGRC shall provide a copy of the report to the aggrieved person(s).

B. Institutional Grievance Redressal Committee (IGRC)

- (i) The complaints not related to departments/schools / center and the grievances not resolved at the DGRC shall be referred to the Institutional Grievance Redressal Committee (IGRC) to be constituted by Head of the HEI, whose composition shall be as follows:
 - (a) Pro-Vice Chancellor / Dean/ Senior academician of HEI – Chairperson.
 - (b) Dean of students/Dean, Students Welfare
 - (c) Two senior academicians other than Chairperson.
 - (d) Proctor / Senior academician
- (ii) The above Committee shall be approved by the statutory body of institution (Executive Council or its equivalent).
- (iii) The Chairperson of IGRC and DGRC shall not be the same. The tenure of the Committee members shall be two years.
- (iv) The quorum for the meetings shall be three, including Chairperson.
- (v) The IGRC shall consider the recommendation of DGRC while giving its recommendations. However, the IGRC shall have the power to review recommendations of the DGRC.
- (vi) The IGRC shall follow the principles of natural justice while deciding the grievances.
- (vii) The IGRC shall send the report and the recommendations to the Head of the HEI within in a period of 15 workings days from the date of receipt of grievance, or appeal or recommendations of the DGRC.
- (viii) The IGRC shall provide a copy of the report to the aggrieved person(s).

C. College Grievance Redressal Committee (CGRC)

- (i) In case of colleges, all complaints shall first be addressed to College Grievance Redressal Committee (CGRC) whose composition shall be as follows:
 - a) Principal of the college -Chairperson
 - b) Two senior faculty members nominated by the principal of the College.
- (ii) The tenure of the members shall be two years.
- (iii) The quorum for the meeting shall be two, including Chairperson.
- (iv) The CGRC shall follow the principles of natural justice while considering the grievances of the students.
- (v) The CGRC shall send the report and recommendations to the Vice-Chancellor of the affiliating university within a period of 15 days of receiving the complaint.

D. University Grievance Redressal Committee (UGRC)

- (i) In case of grievances not resolved by CGRC, it shall be referred to University Grievance Redressal Committee (UGRC) for which the Vice-chancellor of the affiliating university shall constitute a University Grievance Redressal Committee (UGRC) consisting of five members for a individual colleges or a group of colleges keeping in view the location of the college(s). The UGRC shall be constituted by the Vice-chancellor of the affiliating university consisting of :
 - a) A senior Professor of the university – Chairperson
 - b) Dean, Student Welfare or its equivalent - Member
 - c) Three Principals drawn from the affiliating colleges, on rotation basis to be nominated by the Vice-Chancellor – Members
- (ii) The Chairperson and members of the committee shall have a term of two years.
- (iii) The quorum for the meeting shall be two, including Chairperson.

(iv) The CGRC shall follow the principle of normal justice while deciding the grievance of the students.

(v) The CGRC shall send the report and the recommendations to the principal of the college within a period of 15 days of receiving the complaint.

E. Any person aggrieved by the decision of the Institutional Grievance Redressal Committee or University Grievance Redressal Committee may within in a period of six days prefer an appeal to the Ombudsperson.

5. APPOINTMENT, TENURE, REMOVAL AND CONDITIONS OF SERVICES OF OMBUDSPERSON:

(i) Each HEI shall appoint an Ombudsperson for redressal of grievances of students under these regulations.

(ii) The Ombudsperson shall be a person not related to the university and who is a retired Vice-Chancellor, Registrar or a faculty member who has at least ten years of experience as a Professor.

(iii) The Ombudsperson shall not be in any conflict of interest with the university, either before or after his appointment.

(iv) The Ombudsperson, or any member of his immediate family shall not -

(a) hold or have held at any point in the past, any post or, employment in any office of profit in the university;

(b) have any significant relationship, including personal, family, professional or financial, with the university;

(c) hold any position in university by whatever name called, in the administration or governance structure of the university.

(v) The Ombudsperson in a State University shall be appointed by the Executive council of the university on part-time basis from a panel of three names recommended by the search committee consisting of the following members, namely:-

- (a) Nominee of the Governor of the State or his nominee - Chairperson
 - (b) Vice-Chancellor of a University of State to be nominated by the State Government – Member
 - (c) Vice-Chancellor of the concerned State University – Member
 - (d) Registrar of the concerned State University – Secretary (non-voting)
- (vi) The Ombudsperson in a Central University and institution deemed to be university shall be appointed by the Executive Council of the Central University or the equivalent statutory body of the Deemed to be University, as the case may be, on part - time basis from a panel of three member recommended by the search committee consisting of the following members, namely:-

- (a) Nominee of University Grants Commission – Chairperson
- (b) One Vice Chancellor from Central University to be nominated by UGC (for Central Universities) – Member

OR

One Vice Chancellor from institution deemed to be university to be nominated by the UGC (for Deemed to be Universities) - Member

- (c) The Vice Chancellor of the university – Member
 - (d) The Registrar of the university – Secretary (Non-Voting)
- (vii) The Ombudsperson shall be a part time officer appointed for a period of three years from the date he/she assumes the office and may be reappointed for another one term in the same university.
- (viii) The Ombudsperson shall be paid the sitting fee per day as per the norms of the university for hearing the cases, in addition to the reimbursement of the conveyance.

- (ix) The Ombudsperson may be removed on charges of proven misconduct or misbehavior or as defined under these regulations, by the concerned appointing authority i.e. the Executive Council of the University.

6. FUNCTIONS OF OMBUDSPERSON:

- (i) The Ombudsperson shall hear any appeal of an applicant for admission as student or student of the university against the university or institution affiliated to it as the case may be, after the student has availed all remedies available in such institution for redressal of grievance such as IGRC / UGRC;
- (ii) No application for revaluation or remarking of answer sheets shall be entertained by the Ombudsperson. However, the issues of malpractices in the examination and evaluation processes may be referred to the Ombudsperson.
- (iii) Ombudsperson may seek the assistance of any person as amicus curiae, for hearing complaints of alleged discrimination.
- (iv) The Ombudsperson shall make all efforts to resolve the grievances within a period of 30 days of receiving the appeal from the student(s).

7. PROCEDURE FOR REDRESSAL OF GRIEVANCES BY OMBUDSPERSON AND GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE:

- (i) Each institution shall, within a period of three months from the date of issue of this notification, have an online portal where any aggrieved student of that institution may submit an application seeking grievance redressal.
- (ii) On receipt of any online complaint, the institution shall refer the complaint to the appropriate Grievance Redressal Committee, as the case may be, along with its comments within 15 days of receipt of complaint on online portal.
- (iii) The Grievance Redressal Committee, as the case may be, shall fix a date for hearing the complaint which shall be communicated to the institution and the aggrieved person.

- (iv) An aggrieved person may appear either in person or be represented by such person as may be authorized to present his/her case.
- (v) The Grievances not resolved at the appropriate Grievance Redressal Committee(s) shall be referred to the Ombudsperson.
- (vi) The institution shall co-operate with the Ombudsperson or the Grievance Redressal Committee(s), as the case may be, in redressal of grievances and failure to do so may be reported by the Ombudsperson to the Vice Chancellor.
- (vii) On the conclusion of proceedings, the Ombudsperson shall pass such order, with reasons for such order, as may be deemed fit to redress the grievance and provide such relief as may be desirable to the affected party at issue, after giving due hearing to both the parties.
- (viii) Every order under the signature of the Ombudsperson shall be provided to the aggrieved person and the institution and shall be placed on the website of the institution.
- (ix) The institution shall comply with the recommendations of the Ombudsperson. Any recommendations of the Ombudsperson not complied with by the institution shall be reported by the Ombudsperson to the Commission.
- (x) In case of any false or frivolous complaint, the Ombudsperson may recommend appropriate action against the complainant.

8. INFORMATION REGARDING OMBUDSPERSON GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE:

The institution shall provide detailed information regarding provisions of Grievance Redressal Committee(s) and Ombudsperson on their website and in their prospectus prominently.

9. CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE:

The Commission shall in respect of any institution which willfully contravenes these regulations or repeatedly fails to comply with the recommendation of the Ombudsperson or the Grievance Redressal

Committee(s), as the case may be, may proceed to take one or more of the following actions, namely:

- (a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act;
- (b) withholding any grant allocated to the Institution;
- (c) declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programs of the Commission;
- (d) informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not possess the minimum standards for redressal of grievances;
- (e) recommend to the affiliating university for withdrawal of affiliation, in case of a college;
- (f) The Commission may take necessary and appropriate action as it may deemed fit, in case of an institution deemed to be university;
- (g) recommend to the concerned State Government for necessary and appropriate action, in case of a university established or incorporated under a State Act;
- (h) The Commission may take necessary and appropriate actions against any institution for non-compliance.

Provided that no action shall be taken by the Commission under this regulation unless the institution has been given an opportunity to explain its position and an opportunity of being heard has been provided to it.

(Prof. Rajnish Jain)
Secretary


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 29, 2016/आषाढ़ 8, 1938

No. 269]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 29, 2016/ASHADHA 8, 1938

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2016

सं. फा. 1-15/2009(ए.आर.सी.).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (3 का 1956) के अनुच्छेद 26 के उप-अनुच्छेद (1) की धारा (जी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्न विनियमों का सृजन करता है :—

- (1) ये विनियम "उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग अपराध निषेध विनियम, 2016 (तृतीय संशोधन)" के नाम से जाने जाएं।
- (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू माने जाएं।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, "उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग अपराध निषेध, 2009" (इसके उपरान्त प्रमुख विनियमों के सन्दर्भ में) के पैरा 3 के उप शीर्षक "रैगिंग कैसे होती है" 3(झ) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए :—

3(अ). किसी भी छात्र को (नवीन प्रविष्ट या अन्यथा) लक्षित करके रंग, प्रजाति, धर्म, जाति, जातिमूल, लिंग (उभय लैंगिकों सहित) लैंगिक प्रवृत्ति, बाह्य स्वरूप, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीयमूल, भाषा वैशिष्ट्य, जन्म, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना (दंबर्गई एवं बहिष्करण) का कृत्य।

प्रोफेसर जसपाल एस. सन्धू, सचिव (यूजीसी)

[विज्ञापन III/4/असा./149/(113)]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2016

No. F. 1-15-/2009 (ARC).—In exercise of powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following regulations namely:—

- (1) These regulations may be called “Curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions (third amendment), Regulations, 2016.”
 - (2) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.
2. In UGC Regulations on Curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009 (herein-after referred to as the Principal regulations), in Para 3 the following shall be added after 3(i) under heading what constitutes Ragging.—
- 3(j). Any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (fresher or otherwise) on the ground of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity, place of birth, place of residence or economic background.

Prof. JASPAL S. SANDHU, Secy. (UGC)

[ADVT. III/4/Exty./149/(113)]

ANNEXURE III
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI 110 002
UGC REGULATIONS ON CURBING THE MENACE OF RAGGING IN HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 2009.
(Under Section 26 (1)(g) of the University Grants Commission Act, 1956)
Dated 17th June, 2009.
F.1-16/2007(CPP-II)
PREAMBLE.

In view of the directions of the Hon'ble Supreme Court in the matter of "University of Kerala v/s. Council, Principals, Colleges and others" in SLP no. 24295 of 2006 dated 16.05.2007 and that dated 8.05.2009 in Civil Appeal number 887 of 2009, and in consideration of the determination of the Central Government and the University Grants Commission to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging including any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indiscipline activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student, in all higher education institutions in the country, and thereby, to provide for the healthy development, physically and psychologically, of all students, the University Grants Commission, in consultation with the Councils, brings forth this Regulation. In exercise of the powers conferred by Clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely;

1. Title, commencement and applicability.-
2. These regulations shall be called the "UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009".
3. They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. They shall apply to all the institutions coming within the definition of an University under sub section (f) of section (2) of the University Grants Commission Act, 1956, and to all institutions deemed to be a university under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, to all other higher Educational institutions, or elements of such universities or institutions, Including its departments, constituent units and all the premises, whether being Academic, residential, playgrounds, canteen, or other such premises of such Universities, deemed universities and higher educational institutions, whether Located within the campus or outside, and to all means of transportation of Students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of Studies in such universities, deemed universities and higher educational Institutions.
4. Objectives.- To prohibit any conduct by any student or students whether by words spoken or Written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with Rudeness a fresher or any other

student or indulging in rowdy or indisciplined Activities by any student or students which cause or is likely to cause Annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension Thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act Which such student will not in the ordinary course do and which has the effect Of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to Adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, With or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, Authority or superiority by a student over any fresher or any other student; and Thereby, to eliminate ragging in all its forms from universities deemed, Universities and other higher educational institutions in the country by Prohibiting it under these Regulations, preventing its occurrence and punishing Those who indulge in ragging as provided for in these Regulations and the Appropriate law in force.

5. What constitutes Ragging? - Ragging constitutes one or more of any of the Following acts:

- a. any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a Fresher or any other student;
- b. indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which Causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm Or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;
- c. asking any student to do any act which such student will not in the ordinary Course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or Torment or embarrassment so as to adversely affect the Physique or psyche of such fresher or any other student
- d. any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular Academic activity of any other student or a fresher;
- e. exploiting the services of a fresher or any other student for completing the Academic tasks assigned to an individual or a group of students.
- f. any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or Any other student by students
- g. any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual Assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily Harm or any other danger to health or person
- h. any act or abuse by spoken words, emails, post, public insults which would also Include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or Passively participating in the discomfiture to fresher or any other student
- i. any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any Other student with or without intent to derive a sadistic pleasure or showing Off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other Student.

4. Definitions

1. In these regulations unless the context otherwise requires,-
 - a. Act” means, the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956)
 - b. Academic year” means the period from the commencement of admission of Students in any course of study in the institution up to the completion of Academic requirements for that particular year.
 - c. “Anti-Ragging Helpline” means the Helpline established under clause (a) of Regulation 8.1 of these Regulations.

- d. "Commission" means the University Grants Commission;
- e. "Council" means a body so constituted by an Act of Parliament or an Act of any State Legislature for setting, or co-coordinating or maintaining standards in the Relevant areas of higher education, such as the All India Council for Technical Education (AICTE), the Bar Council of India (BCI), the Dental Council of India (DCI), the Distance Education Council (DEC), the Indian

Council of Agricultural Research (ICAR), the Indian Nursing Council (INC), the Medical Council of India (MCI), the National Council for Teacher Education (NCTE), The Pharmacy Council of India (PCI), etc. and the State Higher Education Councils.

f) "District Level Anti-Ragging Committee" means the Committee, headed by the District Magistrate, constituted by the State Government, for the control and Elimination of ragging in institutions within the jurisdiction of the district.

g) "Head of the institution" means the Vice-Chancellor in case of a university or a Deemed to be university, the Principal or the Director or such other designation As the executive head of the institution or the college is referred.

h) "Fresher" means a student who has been admitted to an institution and who is Undergoing his/her first year of study in such institution.

i) "Institution" means a higher educational institution including, but not limited to A university, a deemed to be university, a college, an institute, an institution of National importance set up by an Act of Parliament Or a constituent unit of Such Institution, imparting higher education beyond 12 years of schooling Leading To, but not necessarily culminating in, a degree (graduate, Postgraduate and/or Higher level) and/or to a University diploma.

j) "NAAC" means the National Academic and Accreditation Council established By the Commission under section 12(ccc) of the Act;

k) "State Level Monitoring Cell" means the body constituted by the State Government for the control and elimination of ragging in institutions within The jurisdiction of the State, established under a State Law or on the advice of The Central Government, as the case may be.

- (2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act or in The General Clauses Act, 1897, shall have the meanings respectively assigned To them in the Act or in the General Clauses Act, 1897, as the case may be.

5. Measures for prohibition of ragging at the institution level:-

a) No institution or any part of it thereof, including its elements, including, but not Limited to, the departments, constituent units, colleges, centers of studies and all Its premises, whether academic, residential, playgrounds, or canteen, whether ocated within the campus or outside, and in all means of transportation of Students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of Studies in such institutions, shall permit or condone any reported incident of Ragging in any form; and all institutions shall take all necessary and required Measures, including but not limited to the provisions of these Regulations, to Achieve the objective of eliminating ragging, within the institution or outside,

b) All institutions shall take action in accordance with these Regulations against Those found guilty of ragging and/or abetting ragging, actively or passively, or Being part of a conspiracy to promote ragging.

6. Measures for prevention of ragging at the institution level.-6.1 An institution shall take the

7. following steps in regard to admission or Registration of students; namely,

a) Every public declaration of intent by any institution, in any electronic,

b) audiovisual or print or any other Media, for admission of students to any course of study shall

expressly provide that ragging is totally prohibited in the institution, and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging, whether actively or passively, or being a part of a conspiracy to promote ragging, is liable to be punished in accordance with these Regulations as well as under the provisions of any penal law for the time being inForce.

- c) The brochure of admission/instruction booklet or the prospectus, whether in Print or electronic format, shall prominently print these Regulations in full. Provided that the institution shall also draw attention to any law concerning ragging and its consequences, as may be applicable to the institution publishing Such brochure of admission/instruction booklet or the prospectus. Provided Further that the telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the Important functionaries in the institution, including but not limited to the Head Of the institution, faculty members, members of the Anti-Ragging Committees And Anti-Ragging Squads, District and Sub-Divisional authorities, Wardens of Hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be published In the brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.
- d) Where an institution is affiliated to a University and publishes a brochure of Admission/instruction booklet or a prospectus, the affiliating university shall Ensure that the affiliated institution shall comply with the provisions of clause (a) and clause (b) Of Regulation 6.1 of these Regulations.
- e) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an Affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional Languages known to the applicant, as provided in the English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed by the applicant to The Effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as Well as the provisions of any other law for the time being in Force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments Prescribed, both under penal Laws as well as under these Regulations and also Affirm to the effect that he/she has not been expelled and/or debarred by any Institution and further aver that He/she would not indulge, actively or passively³ In the act or abet the act of Ragging and if found guilty of ragging and/or Abetting ragging, is liable to be Proceeded against under these Regulations or Under any penal law or any other Law for the time being in force and such action Would include but is not limited to Debarment or expulsion of such student.
- g) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an Affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional Languages known to the parents/guardians of the applicant, as provided in the English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed

By the parents/guardians of the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions Of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of The prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that his/her ward has not been expelled and/or debarred by any Institution and further aver that his/her ward would not indulge actively or passively, in the act or abet the Act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, his/her ward is liable to be Proceeded against under these Regulations or under any penal law or any other law for the time being in Force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of his/her wards

- h) The application for admission shall be accompanied by a document in the form of, or annexed to, the School Leaving Certificate/Transfer Certificate/Migration Certificate/Character Certificate reporting on the inter-personal/social behavioral pattern of the applicant, to be issued by the school or institution Last attended by the applicant, so that the institution can thereafter keep watch on the applicant, if admitted, whose behavior has been commented in such document.

i) A student seeking admission to a hostel forming part of the institution, or seeking to reside in any temporary premises not forming part of the institution, including a private commercially managed lodge or hostel, shall have to submit additional affidavits countersigned by his/her parents/guardians in the form Prescribed in Annexure I and Annexure II to these Regulations respectively along with his/her application

i) Before the commencement of the academic session in any institution, the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, such as Hostel Wardens, representatives of students, parents/ guardians, faculty, district administration including the police, to discuss the measures to be taken to prevent ragging in the institution and steps to be taken to identify those indulging in or abetting ragging and punish them.

ii) The institution shall, to make the community at large and the students in particular aware of the Dehumanizing effect of ragging, and the approach of the institution towards those indulging in ragging, Prominently display posters depicting the provisions of penal law applicable to incidents of ragging, and the provisions of these Regulations and also any other law for the time being in force, and the punishments thereof, shall be prominently displayed on Notice Boards of all departments, hostels and other buildings as Well as at places, where students normally gather and at places, known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.

j) The institution shall request the media to give adequate publicity to the law prohibiting ragging and the negative aspects of ragging and the institution's resolve to ban ragging and punish those found guilty without fear or favor.

i) The institution shall identify, properly illuminate and keep a close watch on all Locations known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.

ii) The institution shall tighten security in its premises, especially at vulnerable Places and intense policing By Anti-Ragging Squad, referred to in these Regulations and volunteers, if any, shall be resorted to at such points at odd Hours during the first few months of the academic session.

k) The institution shall utilize the vacation period before the start of the new Academic year to launch a publicity campaign against ragging through posters Leaflets and such other means, as may be desirable or required, to promote the Objectives of these Regulations.

i) The faculties/departments/units of the institution shall have induction Arrangements, including those which anticipate, identify and plan to meet any Special needs of any specific section of students, in place well in advance of the Beginning of the academic year with an aim to promote the objectives of this Regulation.

l) Every institution shall engage or seek the assistance of professional counselors Before the commencement of the academic session, to be available when Required by the institution, for the purposes of offering counseling to fresher's and to other students after the commencement of the academic year.

m) The head of the institution shall provide information to the local police and local Authorities, the details of every privately commercially managed hostels or Lodges used for residential purposes by students enrolled in the institution and The head of the institution shall also ensure that the Anti-Ragging Squad Shall ensure vigil in such locations to prevent the occurrence of ragging therein.

6.2 An institution shall, on admission or enrolment or registration of students, take the following steps, Namely

a) Every fresh student admitted to the institution shall be given a printed leaflet detailing to whom he/she Has to turn to for help and guidance for various purposes including addresses and telephone numbers, so as to enable the student to contact the concerned person at any time, if and when required, of the Anti-Ragging Helpline referred to in these Regulations, Wardens, Head of the institution, all members of the anti-ragging squads and committees, relevant district and police authorities.

- b) The institution, through the leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of These Regulations shall explain to the fresher's, the arrangements made for their Induction and orientation which promote efficient and effective means of Integrating them fully as students with those already admitted o the institution in Earlier years.
- c) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall Inform the fresher's about their rights as bona fide students of the institution and Clearly instructing them that they should desist from doing anything, with or Against their will, even if ordered to by the seniors students, and that any Attempt Of ragging shall be promptly reported to the Anti-ragging Squad or to The Warden or to the Head of the institution, as the case may be.
- d)The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall Contain a calendar of events and activities laid down by the institution to Facilitate and complement familiarization of fresher's with the academic Environment of the institution.
- e) The institution shall, on the arrival of senior students after the first week or after the second week, as the case may be, schedule orientation programmers as Follows, namely (I) joint sensitization programmed and counseling of both fresher's and senior students by a professional counselor, referred to in clause (o) Of Regulation 6.1 of these Regulations; (ii) joint orientation programmed of Freshers and seniors to be addressed by the Head of the institution and the anti –ragging committee ;(iii) organization on a large scale of cultural, sports and Other activities to provide a platform for the fresher's and seniors to interact in The presence of faculty members; (IV) in the hostel, the warden should address All students; and may request two junior colleagues from the college faculty to Assist the warden by becoming resident tutors for a temporary duration.(v) as far As possible faculty members should dine with the hostel residents in their Respective hostels to instill a feeling of confidence among the fresher's.
- f) The Institution shall setup appropriate committees, including the course-in charge, Student advisor, Wardens and some senior students as its members, to actively Monitor, promote and regulate healthy interaction between the fresher's, junior Students and senior students.
- g) Fresher's or any other student(s), whether being Victims, or witnesses, in any incident of ragging, shall be encouraged to report Such occurrence, and the identity of such informants shall be protected and shall Not be subject to any adverse consequence only for the reason for having Reported such incidents.
- h)Each batch of fresher's, on arrival at the institution, Shall be divided into small groups and each such group shall be assigned to a Member of the faculty, who shall interact individually with each member of the Group every day for ascertaining the problems or difficulties, if any,Faced by the fresher in the institution and shall extend necessary help to the fresher in overcoming the same.
- I)It shall be the responsibility of the member of the faculty assigned to the group of fresher's, to coordinate with the Wardens of the hostels and to make surprise visits to the rooms in such hostels, where a member or members of the group are lodged; and such member of faculty shall maintain a diary of his/her interaction with the fresher's under his/her charge.
- j) Fresher's shall be lodged, as far as may be, in a separate hostel block, and where such facilities are not available, the institution shall ensure that access of seniors to accommodation allotted to fresher's is strictly monitored by wardens, security guards and other staff of the institution.
- k) A round the clock vigil against ragging in the hostel premises, in order to prevent ragging in the hostels after the classes are over, shall be ensured by the institution.
- l) It shall be the responsibility of the parents/guardians of fresher's to promptly bring any instance of ragging to the Notice of the Head of the Institution.
- m) Every student studying in the institution and his/her parents/guardians shall provide the specific affidavits required under clauses (d), (e) and (g) of Regulation 6.1 of these Regulations at the time of admission or registration, as the case may be, during each academic

year. n) Every institution shall obtain the affidavit from every student as referred to above in clause (m) of Regulation 6.2 and maintain a proper record of the same and to ensure its safe upkeep thereof, including maintaining the copies of the affidavit in an electronic form, to be accessed easily when required either by the Commission or any of the Councils or by the institution or by the affiliating University or by any other person or organisation authorized to do so. o) Every student at the time of his/her registration shall inform the institution about his/her place of residence while pursuing the course of study, and in case the student has not decided his/her place of residence or intends to change the same, the details of his place of residence shall be provided immediately on deciding the same; and specifically in regard to a private commercially managed lodge or hostel where he/she has taken up residence. p) The Head of the institution shall, on the basis of the information provided by the student under clause (o) of Regulation 6.2, apportion sectors to be assigned to members of the faculty, so that such member of faculty can maintain vigil and report any incident of ragging outside the campus or en route while commuting to the institution using any means of transportation of students, whether public or private. q) The Head of the institution shall, at the end of each academic year, send a letter to the parents/guardians of the students who are completing their first year in the institution, informing them about these Regulations and any law for the time being in force prohibiting ragging and the punishments thereof as well as punishments prescribed under the penal laws, and appealing to them to impress upon their wards to desist from indulging in ragging on their return to the institution at the beginning of the academic session next.

6.3

Every institution shall constitute the following bodies; namely, a) every institution shall constitute a Committee to be known as the Anti-Ragging Committee to be nominated and headed by the Head of the institution, and consisting of representatives of civil and police administration, local media, Non Government Organizations involved in youth activities, representatives of faculty\members, representatives of parents, representatives of students belonging to the fresher's category as well as senior Students, non-teaching staff; and shall have a diverse mix of membership in terms of levels as well as gender. b) It shall be the duty of the Anti-Ragging Committee to ensure compliance with the provisions of these Regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; and Also to monitor and oversee the performance of the Anti- Ragging Squad in prevention of ragging in the institution. c) Every institution shall also constitute a smaller body to be known as the Anti- Ragging Squad to be nominated by the Head of the Institution with such representation as may be considered Necessary for maintaining vigil, oversight and patrolling functions and shall remain mobile, alert and active at all times. Provided that the Anti-Ragging Squad shall have representation of various members of the campus community and shall have no outside representation. d) It shall be the duty of the Anti-Ragging Squad to be called upon to make surprise raids on hostels, and other places vulnerable to incidents of, and having the potential of, ragging and shall be empowered to inspect such places. e) It shall also be the duty of the Anti-Ragging Squad to conduct an on-the-spot enquiry into any incident of ragging referred to it by the Head of the institution or any member of the faculty or any member of the staff or any student or any parent or guardian or any employee of a service provider or by any other person, as the case may be; and the enquiry report along with recommendations shall be submitted to the Anti-Ragging Committee for action under clause (a) of Regulation 9.1. Provided that the Anti-Ragging Squad shall conduct such enquiry observing a fair and transparent procedure and the principles of natural justice and after giving adequate opportunity to the student or students accused of ragging and other witnesses to place before it the facts, documents and views concerning the incident of ragging, and considering such Other relevant information as may be required. f) Every institution shall, at the end of each academic year, in order to promote the objectives of these Regulations, constitute a Mentoring Cell consisting of students volunteering to be Mentors for fresher, in the succeeding academic year; and there shall be as many levels or tiers of Mentors as the number of batches in the institution, at the rate of one Mentor for six fresher and

one Mentor of a higher level for six Mentors of the lower level. g) Every University shall constitute a body to be known as Monitoring Cell on Ragging, which shall coordinate with the affiliated colleges and Institutions under the domain of the University to achieve the objectives of these Regulations; and the Monitoring Cell shall call for reports from the Heads of institutions in regard to the activities of the Anti-Ragging Committees, Anti - Ragging Squads, and the Mentoring Cells at the institutions, and it shall also Keep itself abreast of the decisions of the District level Anti-Ragging Committee headed by the District Magistrate. h) The Monitoring Cell shall also review the efforts made by institutions to publicize ant ragging measures, soliciting of affidavits from parents/guardians and from students, each academic year, to abstain from ragging activities or willingness to be penalized for violations; and shall function as the prime mover for initiating action on the part of the appropriate authorities of the university for amending the Statutes or Ordinances or Byelaws to facilitate the implementation of ant ragging measures at the level of the institution.6.4 Every institution shall take the following other measures, namely; a) each hostel or a place where groups of students reside, forming part of the institution, shall have a full-time Warden, to be appointed by the institution as per the Eligibility criteria laid down for the post reflecting both the command and control aspects of maintaining discipline and preventing incidents of ragging within the hostel, as well as the softer skills of counseling and communicating with the youth outside the class-room situation; and who shall reside within the hostel, or at the very least, in the close vicinity thereof. b) The Warden shall be accessible at all hours and be available on telephone and other modes of communication, and for the purpose the Warden shall be provided with a mobile phone by the institution, the number of which shall be publicized among all students residing in the hostel.c) The institution shall review and suitably enhance the powers of Wardens and The security personnel posted in hostels shall be under the direct control of the Warden and their performance shall be assessed by them. d) The professional counselors referred to Under clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations shall, at the time of admission, counsel fresher's and/or any other student(s) desiring counseling, in order to prepare them for the life ahead, particularly in Regard to the Life in hostels and to the extent possible, also involve parents and teachers in the counseling sessions. e) The institution shall undertake measures for extensive publicity against ragging by means of audio-visual aids, counseling sessions, workshops, painting and design competitions among students and such other Measures, as it may deem fit. f) In order to enable a student or any person to communicate with the Anti- Ragging Helpline, every Institution shall permit unrestricted access to mobile phones and public phones in hostels and campuses, other than in classrooms, seminar halls, library, and in such other places that the institution may deem it necessary to restrict the use of phones. g) The faculty of the institution and its non- teaching staff, which includes but is not limited to the administrative staff, contract employees, security guards and Employees of service providers providing services within the institution shall be sensitized towards the ills of ragging, its prevention and the consequences thereof. h) The institution shall obtain an undertaking from every employee of the institution including all teaching and non-teaching members of staff, contract labor employed in the premises either for running canteen or as watch and ward staff or for cleaning or Maintenance of the buildings/lawns and employees, of service providers providing services within the institution, that he/she would report promptly any case of ragging which comes to his/her notice. i) The institution shall make a provision in the service rules of its employees for issuing certificates of appreciation to such members of the staff who report incidents of ragging, which will form part of their service record. j) The institution shall give necessary instructions to the employees of the canteens and messing, whether that of the institution or that of a service provider providing this service, or their employers, as the case may be, to keep a strict vigil in the area of their work and to report the incidents of ragging to the Head of the institution or members of the Ragging quad or members of the Anti-Ragging Committee or the Wardens, as may be required. k) All Universities awarding a degree in education at any level, shall be required to

ensure that institutions imparting instruction in such courses or conducting training programmed for teachers include inputs relating to anti ragging and the appreciation of the relevant human rights, as well as inputs on topics regarding sensitization against corporal punishments and checking of bullying amongst students, so that every teacher is equipped to handle at least the rudiments of the counseling approach. l) Discreet random surveys shall be conducted amongst the fresher's every fortnight during the first three months of the academic year to verify and crosscheck whether the institution is indeed free of ragging or not and for the Purpose the institution may design its own methodology of conducting such surveys. m) The institution shall cause to have an entry, apart from those relating to general conduct and behavior, made in the Migration/Transfer Certificate issued to the student while leaving the institution, as to whether the Student has been punished for committing or abetting an act of ragging, as also whether the student has displayed persistent violent or aggressive behavior or any inclination to harm others, during his course of study in the institution. n) Notwithstanding anything contained in these Regulations with regard to Obligations and responsibilities pertaining to the authorities or members of bodies prescribed above, it shall be the general collective responsibility of all levels and sections of authorities or functionaries including members of the faculty and employees of the institution, whether regular or temporary, and Employees of service providers providing service within the institution, to prevent or to act promptly against the occurrence of ragging or any incident of ragging which comes to their notice. o) The Heads of institutions affiliated to a University or a constituent of the University, as the case may be, shall, during the First three months of an academic year, submit a weekly report on the status of compliance with Anti-Ragging measures under these Regulations, and a monthly report on such status thereafter, to the Vice-Chancellor of the University to which the institution is affiliated to or recognized by. p) The Vice Chancellor of each University, shall submit fortnightly reports of the University, including those of the Monitoring Cell on Ragging in case of an affiliating university, to the State Level Monitoring Cell.

7. Action to be taken by the Head of the institution.- On receipt of the recommendation of the Anti Ragging Squad or on receipt of any information concerning any reported incident of ragging, the Head of institution shall immediately determine if a case under the penal laws is made out and if so, either on his own or through a member of the Anti-Ragging Committee authorised by him in this behalf, proceed to file a First Information Report (FIR), within twenty four hours of receipt of such information or recommendation, with the police and local authorities, under the appropriate penal provisions relating to one or more of the following, namely; i. Abetment to ragging; ii. Criminal conspiracy to rag; iii. Unlawful assembly and rioting while ragging; IV. Public nuisance created during ragging; v. Violation of decency and morals through ragging; VI. Injury to body, causing hurt or grievous hurt; vii. Wrongful restraint; viii. Wrongful confinement; ix. Use of criminal force; x. Assault as well as sexual offences or unnatural offences; xi. Extortion; xii. Criminal trespass; xiii. Offences against property xiv. Criminal intimidation; xv. Attempts to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s); xvi. Threat to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s); xvii. Physical or psychological humiliation; xviii. All other offences following from the definition of "Ragging". Provided that the Head of the institution shall forthwith report the occurrence of the incident of ragging to the District Level Anti-Ragging Committee and the Nodal officer of the affiliating University, if the institution is an affiliated institution. Provided further that the institution shall also continue with its own enquiry initiated under clause 9 of these Regulations and other measures without waiting for action on the part of the police/local authorities and such remedial action shall be initiated and completed immediately and in no case later than a period of seven days of the reported occurrence of the incident of ragging.

8. Duties and Responsibilities of the Commission and the Councils.- 8.1 The Commission shall, with regard to providing facilitating communication of information regarding incidents of ragging in any institution, take the following steps, namely; a) The Commission shall establish, fund and operate, a toll-free Anti-Ragging Helpline,

operational round the clock, which could be accessed by students in distress owing to ragging related incidents. b) Any distress message received at the Anti- Ragging Helpline shall be simultaneously relayed to the Head of the Institution, the Warden of the Hostels, the Nodal Officer of the affiliating University, if the incident reported has taken place in an institution affiliated to a University, the concerned District authorities and if so required, the District Magistrate, and the Superintendent of Police, and shall also be web enabled so as to be in the public domain simultaneously for the media and citizens to access it. c) The Head of the institution shall be obliged to act immediately in response to the information received from the Anti-Ragging Helpline as at sub-clause (b) of This clause. d) The telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in every institution, Heads of institutions, faculty members, members of the anti-ragging committees and anti ragging squads, district and sub-divisional authorities and state authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be widely disseminated for access or to seek help in emergencies. e) The Commission shall maintain an appropriate data base to be created out of affidavits, affirmed by each student and his/her parents/guardians and stored electronically by the institution, either on its or through an agency to be designated by it; and such database shall also function as a record of ragging complaints received, and the status of the action taken thereon. f) The Commission shall make available the database to a non-governmental agency to be nominated by the Central Government, to build confidence in the public and also to provide information of non compliance with these Regulations to the Councils and to such bodies as may be authorized by the Commission or by the Central Government. 8.2 The Commission shall take the following regulatory steps, namely; a) The Commission shall make it mandatory for the institutions to incorporate in their prospectus, the directions of the Central Government or the State Level Monitoring Committee with regard to prohibition and consequences of ragging, and that noncompliance with these Regulations and directions so provided, shall be considered as lowering of academic standards by the institution, therefore making it liable for appropriate action. b) The Commission shall verify that the institutions strictly comply with the requirement of getting the affidavits From the students and their parents/guardians as envisaged under these Regulations. c) The Commission shall include a specific condition in the Utilization Certificate, in respect of any financial assistance or grants-in-aid to any institution under any of the general or special schemes of the Commission, that the Institution has complied with the anti-ragging measures. d) Any incident of ragging in an institution shall adversely affect its accreditation, ranking or grading by NAAC or by any other authorized accreditation agencies while assessing the institution for accreditation, ranking or grading purposes. e) The Commission May accord priority in financial grants-in-aid to those institutions, otherwise eligible to receive grants under section 12B of the Act, which report a blemish less record in terms of there being no reported. Incident of ragging. f) The Commission shall constitute an Inter-Council Committee, consisting of Representatives of the various Councils, the Non-Governmental agency responsible for monitoring the Database maintained by the Commission under clause (g) of Regulation 8.1 and such other bodies in Higher Education, to coordinate and monitor the anti-ragging measures in institutions across the country and to make recommendations from time to time; and shall meet at least once in six months each year. g) The Commission shall institute an Anti-Ragging Cell within the Commission as an institutional mechanism to provide secretarial support for collection of information and monitoring, and to coordinate with the State Level Monitoring Cell and University level Committees for effective implementation of anti-ragging measures, and the Cell shall also coordinate with the Non-Governmental agency responsible for monitoring the database maintained by the Commission appointed under clause (g) of Regulation 8.1. 9. Administrative action in the event of ragging.- 9.1 The institution shall punish a student found guilty of ragging after following the procedure and in the manner prescribed herein under: a) The Anti-Ragging Committee of the institution shall take an Appropriate decision, in regard to punishment or otherwise, depending on the facts of each incident of ragging and nature and

gravity of the incident of ragging established in the recommendations of the Anti- Ragging Squad. b) The Anti-Ragging Committee may, depending on the nature and gravity of the guilt Established by the Anti-Ragging Squad, award, to those found guilty, one or more of the following punishments, namely; I. Suspension from attending classes and academic privileges. ii. Withholding/ withdrawing scholarship/ fellowship and other benefits. iii. Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation process. iv. Withholding results. v. Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc. VI. Suspension/ expulsion from the hostel. vii. Cancellation of admission. viii. Rustication from the institution for period ranging from one to four semesters. ix. Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution for a specified period. Provided that where the persons committing or abetting the act of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment. c) An appeal against the order of punishment by the Anti-Ragging Committee shall lie, i. in case of an order of an institution, affiliated to or constituent part, of a University, to the Vice- Chancellor of the University; ii. In case of an order of a University, to its Chancellor. Iii. in case of an institution of national importance created by an Act of Parliament, to the Chairman or Chancellor of the institution, as the case may be. 9.2 Where an institution, being constituent of, affiliated to or recognized by a University, fails to comply with any of the provisions of these Regulations or fails to curb ragging effectively, such University may take any one or more of the following actions, namely; i. Withdrawal of affiliation/recognition or other privileges conferred. ii. Prohibiting such institution from presenting any student or students then undergoing any programmed of study therein for the award of any degree/diploma of the University. Provided that where an institution is prohibited from presenting its student or students, the Commission shall make suitable arrangements for the other students so as to ensure that such students are able to pursue their academic studies. iii. Withholding grants allocated to it by the university, if any iv. Withholding any grants channelized through the university to the institution. v. Any other appropriate penalty within the powers of the university. 9.3 Where in the opinion of the appointing authority, a lapse is attributable to any member of the faculty or staff of the institution, in the matter of reporting or taking prompt action to prevent an incident of ragging or who display an apathetic or insensitive attitude towards complaints of ragging, or who fail to take timely steps, whether required under these Regulations or otherwise, to prevent an incident or incidents of ragging, then such authority shall initiate departmental disciplinary action, in accordance with the prescribed procedure of the institution, against such member of the faculty or staff. Provided that where such lapse is attributable to the Head of the institution, the authority designated to appoint such Head shall take such departmental disciplinary action; and such action shall be without prejudice to any Action that may be taken under the penal laws for abetment of ragging for failure to take timely steps in the prevention of ragging or punishing any student found guilty of ragging. 9.4 The Commission shall, in respect of any institution that fails to take adequate steps to prevent ragging or fails to act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators or incidents of ragging suitably, take one of more of the following measures, namely; i. Withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act. ii. Withholding any grant allocated. iii. Declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmers of the Commission. iv. Informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not Possess the minimum academic standards. v. Taking such other action within its powers as it may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the Act for such duration of time as the institution complies with the provisions of these Regulations. Provided that the action taken under this clause by the Commission against any

Institution shall be shared with all Councils.

(Dr. R.K. Chauhan)

Secretary

To,

The Assistant Controller,

Publication Division, Govt. of India,

Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation,

Civil Lines Delhi -110 054